दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 95 भारत के हैं

रियल टाइम ग्लोबल टैम्परेचर रैंकिंग के अनुसार, भारत दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म देश है

- महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं।
- भारतीय मौसम विभाग ने अभी और तेज़ गर्म लू चलने की चेतावनी जारी की है और कहा कि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 अप्रैल। भारत वर्तमान में गर्मी की लहर अन्तर्राष्ट्रीय का केन्द्र बना हुआ है। रियल-टाइम ग्लोबल तापमान रैंकिंग के अनुसार, शनिवार को दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 95 शहर भारत के हैं।

24 अप्रैल शाम 5:00 बजे के डेटा से उपमहाद्वीप के बड़े हिस्सों में जारी हीटवेव की तीव्रता और व्यापकता उजागर होती है।

मध्य भारत से लेकर सिंधु- गंगा मैदानों तक, दर्जनों शहरों में तापमान 40 से. के पार पहुँच गया है, और कई स्थान लगभग 45 से. के निशान के करीब हैं।

इस सूची में सिर्फ बड़े शहर ही नहीं, बल्कि छोटे शहर भी शामिल हैं, जो दर्शाते हैं कि हीटवेव की स्थिति कितनी व्यापक और गहरी हो गई है।

महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्य सबसे अधिक प्रभावित हैं, और इन राज्यों के कई शहर ग्लोबल टॉप 100 में प्रमुखता से शामिल हैं।

इतनी विशाल भौगोलिक सीमा में अत्यधिक गर्मी की उपस्थिति वर्तमान मौसम की गंभीरता को उजागर करती है।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, इस गर्मी की वजह कई कारक हैं, जिनमें लगातार शुष्क हवाएँ, साफ आकाश और देर से प्री-मॉनसून गतिविधि शामिल हैं।

अच्छी वर्षा और बादलों की कमी के कारण दिन में तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जबकि गर्म रातें किसी भी प्रकार की ठंडक की संभावना को रोक रही हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पहले ही कई क्षेत्रों में हीटवेव की चेतावनी जारी कर दी है और बताया है कि यह स्थिति आने वाले दिनों में बनी रह सकती है।

इन तापमानों के लगातार संपर्क में रहने से हीट-संबंधी बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है, विशेष रूप से वृद्धों, बच्चों और धूप में काम करने वाले कामगारों में।

वर्तमान स्थिति को विशेष रूप से चिंताजनक बनाने वाली बात यह है कि यह गर्मी पूरे देश में एक साथ महसूस हो रही है। स्थानीय गर्मी की घटनाओं के विपरीत, यह लहर कई राज्यों में एक साथ प्रभावी है, जिससे हमारे शहर बड़ी संख्या में वैश्विक अत्यधिक तापमान रैंकिंग में शामिल हो रहे हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के पैटर्न अब प्राय: होने लगे हैं, जो व्यापक जलवायु परिवर्तन और बढ़ते बेसलाइन तापमान की ओर संकेत करते हैं। शहरी हीट आइलैंड प्रभाव, घटता हरा-भरा आवरण और बदलता मौसम तंत्र भी कई क्षेत्रों में इस प्रभाव को बढ़ा रहे हैं।इस निर्मम गर्मी के बावजूद, कुछ राहत की संभावना है। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में आने वाले कुछ दिनों में बिजली गिरने और तेज़ हवाओं की संभावना है, जो अस्थायी राहत ला सकती है।

लेकिन तापमान में बड़ी और स्थायी गिरावट तब तक नहीं होने की संभावना है, जब तक कि मजबूत प्री-मॉनसून सिस्टम या मॉनसून आगे न बढ़े।

फिलहाल, भारत पृथ्वी पर सबसे गर्म देश है। यह असाधारण तथ्य न केवल वर्तमान हीटवेव की तत्कालता को दर्शाता है, बल्कि गर्म होती दुनिया में चरम मौसम की बढ़ती चुनौती को भी उजागर करता है।

बंगाल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सेक्टर-15 की निवासी, कहती हैं कि यह स्थिति निवासियों के लिए काफी असुविधाजनक है।

किरन शेरावत, जो कोरोना अपार्टमेंट्स, सेक्टर-37 की निवासी हैं, ने कहा कि उनकी सहायिका चुनाव के लिए कोलकाता गई हैं और उन्हें नहीं पता कि कब वापस आएंगी। अन्य निवासी भी इस असुविधा की पुष्टि करते हैं।वीना गुप्ता, अनंत राज एस्टेट, सेक्टर-63 की निवासी, कहती हैं, ''हमारी घरेलू सहायिका भी बंगाल गई है। उसकी अनुपस्थिति में किसी नई सहायिका को ढूंढना मुश्किल हो गया है। हमें उम्मीद है कि वह चुनाव खत्म होने के बाद जल्दी लौटेगी।'' सैक्टर-40 की दिव्या बताती हैं कि उनकी सहायिका 10 दिन पहले चली गई थी। उन्हें बर्तन धोने, झाड़ू-पोंछा और सफाई करने के लिए कोई नहीं मिला। कुछ लोगों के लिए घर की मदद न होना और भी तनावपूर्ण हो गया है। सुनिता पांचाल, राहेजा अपार्टमेंट्स, सैक्टर-31 की निवासी, कहती हैं कि हमारी सहायिका केवल सफाई के लिए नहीं, बल्कि पूरे घर के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होती हैं। हालांकि निवासियों को पता है कि यह अस्थायी समस्या है, लेकिन इससे उनकी दिनचर्या पर असर पड़ रहा है।कामकाजी पेशेवरों के लिए स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है, क्योंकि अब उन्हें ऑफिस के काम के साथ-साथ घर के सभी काम भी संभालने पड़ रहे हैं।

बार न्यायिक कार्य बहिष्कार पर पुर्नविचार करे, कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं करे- हाई कोर्ट

हाई कोर्ट की लार्जर बैंच ने एक सुनवाई में कहा कि न्यायिक कार्य से दूरी न्याय व्यवस्था के हित में नहीं

- हाई कोर्ट ने कहा कि बार पदाधिकारियों ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष शपथ पत्र में यह आश्वासन दिया था कि वे न्यायिक कार्य का बहिष्कार नहीं करेंगे। लिखित आश्वासन की पालना की जानी चाहिए।

जयपुर, 24 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन की ओर से शनिवार को कार्य दिवस घोषित करने का विरोध करने और न्यायिक कार्य बहिष्कार पर नाराजगी जताई है। वहीं बार पदाधिकारियों को सुझाव दिया है कि वे न्यायिक कार्य बहिष्कार के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और न्यायालय की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि न्यायिक कार्य से दूरी बनाना न्याय व्यवस्था के हित में नहीं है।

इसके साथ ही, वकीलों को चेतावनी दी कि उन्हें कार्रवाई के लिए बाध्य नहीं किया जाए। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा, जस्टिस भुवन गोयल और जस्टिस समीर जैन की लार्जर बेंच ने यह टिप्पणी शनिवार को एक मुकदमे में सुनवाई के दौरान कही।

सीजे ने कहा कि लार्जर बेंचों को इसलिए बनाया गया था, ताकि लंबित और महत्वपूर्ण मामलों का प्रभावी निस्तारण हो सके, लेकिन हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा न्यायिक कार्य बहिष्कार के कारण अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति रही है।

हम यहां पर केसों की सुनवाई के लिए बैठे हैं, लेकिन न तो पैरवी के लिए महाधिवक्ता, न वरिष्ठ अधिवक्ता और न ही सरकारी अधिवक्ता हैं। जबकि बार पदाधिकारियों ने 2021 में पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष शपथ पत्र दिया था और उसमें यह आश्वासन दिया था कि वे न्यायिक कार्य का बहिष्कार नहीं करेंगे।

जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लिखित आश्वासन दिया गया है, तब उसका पालन भी किया जाना चाहिए। वीसी से पेश वकील कर रहे हैं कि वे व्यक्तिश: पेश नहीं हो पा रहे हैं। जिससे जाहिर है कि उन्हें रोका जा रहा है। यह कोर्ट की अवमानना है। इसके साथ ही उन्होंने आदेश की कॉपी बीसीआई सहित, बार एसोसिएशन को भी भेजी है। दूसरी ओर वकीलों ने बार-बेंच के बीच गतिरोध बताते हुए एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा के तबादले की मांग करते हुए यहां स्थायी सीजे नियुक्त करने की मांग की है। हाईकोर्ट बार के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा का कहना है कि नियमानुसार स्थानीय व्यक्ति को सीजे नहीं बनाया जा सकता।

गौरतलब है कि सीजेआई के जयपुर में रालसा के सेमिनार में शामिल होने के चलते जोधपुर के सभी न्यायाधीशों ने जयपुर बेंच में बैठकर ही मामलों में सुनवाई की थी।

अमेरिका व ईरान...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि विदेश मंत्री अब्बास अराघची की इस्लामाबाद यात्रा क्षेत्रीय मुद्दों या व्यापक कूटनीतिक बातचीत के लिए थी। अराघची ने घोषणा की कि वे पाकिस्तान से ओमान और रूस भी जाएंगे।

अराघची की यात्रा महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह सच है कि वह वास्तव में ईरान में नीति निर्माता नहीं हैं। जब अराघची ने बिना अनुमति यह घोषणा की कि होर्मुज़ स्ट्रेट सामान्य यातायात के लिए खुला है, तो कट्टर रुख वाले ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स (आईआरजीसी) के नेताओं ने इस बात को खारिज कर दिया।

इसलिए, इस समय अराघची के साथ कोई निर्णायक वार्ता संभव नहीं है, जब तक कि ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स इसका अनुमोदन न करें। फिर भी, अराघची अपने देश के लिए सबसे अनुभवी और कुशल वार्ताकारों में से एक माने जाते हैं।

अराघची को कम से कम बीस वर्षों का कूटनीतिक अनुभव है और वे राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में बहुराष्ट्रीय परमाणु समझौते (जेसीपीओए) की महत्वपूर्ण वार्ता में शामिल थे। डोनाल्ड ट्रम्प ने इस समझौते को रद्द कर दिया, जिससे ईरान केवल सहमत सीमा तक यूरेनियम संवर्धन करने की बाध्यता से मुक्त हो गया।

- वार्ता शुरु करने में जितना भी समय लग रहा है वह ईरान को पुनः सेना व सैन्य सामग्री को सुसज्जित करने में सहायक हो रहा है और सैन्य बल मजबूत करने से ईरान की युद्ध की तैयारी पूरी हो रही है।

अब पीछे मुड़कर देखें तो, ट्रम्प का जेसीपीओए को पूरी तरह अस्वीकार करना वर्तमान गतिरोध और टकराव का सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रतीत होता है। समझौते के रद्द होने के बाद और जब ईरान अब केवल 3.6 प्रतिशत तक यूरेनियम संवर्धन के नियम से बंधा नहीं था तो ईरान ने तेजी से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया और विशाल भंडार बना लिया।

अब ट्रम्प की चुनौती यह है कि वह एक बार बोतल से बाहर आ चुके जिन्न को वापस बोतल में कैसे बंद करें। यह बेहद कठिन है, क्योंकि ईरान ने एक स्वतंत्रता का स्वाद चखा है जिसे अब छोड़ना नहीं चाहता।

इसके अलावा, अमेरिकी सशस्त्र हमलों को रोकने में ईरान की बड़ी सफलता और छोटे हथियारों में हासिल लाभ के कारण, ईरान पर ट्रम्प आसानी से नहीं काबू कर सकते।

अमेरिका द्वारा संघर्षविराम को बार-बार बढ़ाने के कारण, ईरान सर्वोत्तम स्थिति में है। वे इस समय का उपयोग मिसाइल और ड्रोन उत्पादन बढ़ाने में कर सकते हैं। अमेरिका दूसरी ओर सख्त समय सीमा के दबाव में है।

अमेरिकियों के लिए दांव ऊंचे हो रहे हैं। घरेलू महंगाई आम जनता के बीच असंतोष बढ़ा रही है। सहयोगियों ने अमेरिका के पक्ष में कदम नहीं रखा और वैश्विक अर्थव्यवस्था गिर रही है, जबकि स्थिर व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप अमेरिका पर है।

एक तरह से, ट्रंप खुद को उस कठिन स्थिति में पाकर फंस गए हैं, जिसमें उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कभी प्रवेश नहीं करने की बात कही थी। उनके उत्साही एमएजीए समर्थक भी उन्हें छोड़ रहे हैं। संक्षेप में, इस एक असावधान कदम के कारण उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल की संभावनाओं को कमज़ोर कर दिया है।

भारत...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बढ़ाने और वैकल्पिक विवाद समाधान से मुकदमों का बोझ कम करने में सहायता मिलती है।

राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा कि आमजन को जागरूक करने एवं सुलभ न्याय पहुंचाने में रालसा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं, लोक अदालतों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के अनुभव से मध्यस्थता के जरिए पुराने विवादों का निस्तारण किया जा रहा है।

कार्यक्रम के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट के नवाचार यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम को लॉन्च किया गया तथा सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स की संकलित पुस्तक का विमोचन किया गया। साथ ही, विधिक सेवाओं को अधिक सुलभ और सशक्त बनाने के लिए मल्टी यूटिलिटी वाहनों को रवाना किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ट जजेज़ के पदाधिकारीगण, राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में विधि विद्यार्थी उपस्थित थे।

बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव, 11 अतिरिक्त पुलिस पर्यवेक्षक तैनात

- ये नए पुलिस पर्यवेक्षक अन्य राज्यों से बुलाए गए हैं
- पहले चरण में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी हिंसा की कुछ घटनाएं हुई थी इसलिए इस बार आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है।

कोलकाता, 25 अप्रैल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आयोग ने शनिवार को घोषणा की कि 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए 11 अतिरिक्त पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। दूसरे चरण में राज्य की 142 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे।

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये सभी 11 नए पुलिस पर्यवेक्षक अन्य राज्यों से बुलाए गए हैं। इनका मुख्य कार्य दूसरे चरण की चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष बनाना है।

प्रशासन इस बार सुरक्षा में रत्ती भर भी ढि लाई नहीं बरतना चाहता। न्यूज एजेंसी आईएएनएस को एक अधिकारी ने बताया, आयोग का लक्ष्य दूसरे चरण में तनाव की किसी भी संभावना को पूरी तरह समाप्त करना है। यही कारण है कि पुलिस पर्यवेक्षक की संख्या में इजाफा किया गया है। हालांकि 23 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, लेकिन फिर भी छिटपुट हिंसा और तनाव की कुछ घटनाएं सामने आई थीं। निर्वाचन आयोग दूसरे चरण में ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति नहीं चाहता।

इन 11 अतिरिक्त अधिकारियों की नियुक्ति के साथ ही, पश्चिम बंगाल में तैनात कुल पुलिस पर्यवेक्षकों की संख्या अब बढ़ कर 95 हो गई है। आयोग ने शुरुआत में इस चुनाव के लिए 84 पर्यवेक्षक तैनात किए थे। अब इस संख्या को और बढ़ा दिया गया है। संवेदनशील इलाकों की पहचान कर ली गई है। वहां अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बाहरी राज्यों से आए इन अधिकारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य पुलिस को सौंपी गई है।

इसके इतर, चुनाव आयोग ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर पुलिस जिले के पांच पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के भी आदेश दिए गए हैं। निलंबित होने वाले अधिकारियों में एक एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एक सब-डिवीजन पुलिस अधिकारी शामिल हैं।

जयराम रमेश ने पवन खेड़ा का समर्थन किया

- उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी गुवाहाटी हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जायेगी।

नई दिल्ली, 25 अप्रैल। कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद पवन खेड़ा का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पवन खेड़ा के साथ मजबूती से खड़ी है और हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की प्रक्रिया चल रही है।

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा द्वारा दर्ज कराए गए आपराधिक मामले से जुड़ा है। पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिनिकी भुइयां सरमा पर कई पासपोर्ट रखने और विदेश में संपत्तियां होने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में पवन खेड़ा और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

भाजपा ने अब...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन पर आरोप लगाया गया है कि वे उन्हें हाल ही में आवंटित आधिकारिक आवास, 95, लोदी एस्टेट में ''शीश महल-2'' बनाने की योजना बना रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और दिल्ली लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को ''दिल्ली का रहमान डकैत'' बताया और कहा कि वे ''साधारण आदमी की छवि दिखाकर, विलासिता भरी जिंदगी जी रहे हैं।'' वर्मा ने 95, लोदी एस्टेट की एक ''आधुनिक ट्रांजिश्नल डिज़ाइन'' की रूपरेखा साझा की, जिसमें फॉयर, लिविंग रूम, लाउंज, बैठक कक्ष और कस्टम फर्नीचर व सजावट के सामान शामिल हैं। आप ने तुरंत इन आरोपों को नकारा और वर्मा के खिलाफ 95, लोदी एस्टेट की झूठी जानकारी और तस्वीरें प्रचारित करने के लिए मानहानि का केस दायर करने की धमकी दी।

इस बीच, पंजाब भाजपा , आप के विभाजन से उत्साहित है। राज्य भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने कहा कि सांसदों का पार्टी छोड़ना केजरीवाल की तानाशाही प्रवृत्तियों का परिणाम है और सत्तारुढ़ पार्टी पर आरोप लगाया कि वह ''उधार के नेताओं'' की ताकत पर टिकी है। हाल ही में हुए उपचुनावों में, आप ने ऐसे उम्मीदवार उतारे, जिन्होंने अन्य पार्टियों से आकर, आप जॉइन की थी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने भी केजरीवाल पर हमला बोला और कहा कि बहुत से नेताओं ने आप छोड़ दी थी, जिनमें अशुतोष, शाज़िया इल्मी, किरण बेदी और कुमार विश्वास जैसे नाम शामिल हैं। चुघ ने कहा: ''पंजाब के लोग पहले ही अपना मन बना चुके हैं। अलविदा केजरीवाल, अलविदा मान।''

- भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरूण चुघ के अनुसार, पंजाब की जनता ने मन बना लिया है और कह रही है ''गुडबाय केजरीवाल, गुडबॉय मान''
- इस संदर्भ में, मुख्यमंत्री मान राष्ट्रपति मुर्मू से मिले हैं, सांसदों को ''डिस्क्वालिफाय'' करने हेतु अपना केस प्रस्तुत करने के लिए।

एक ही दिन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने चड्ढा की छवि एक सुलभ और आम जनता को समर्पित नेता के रूप में बनाई।

राज्यसभा में जैन ज़ैड केन्द्रित मुद्दों पर उनका फोकस पारंपरिक राजनीति और युवा आकांक्षाओं के बीच पुल बनाने में मददगार साबित हुआ।?

उन्हें एक अलग तरह के नेता के रूप में देखा गया। यहाँ तक कि जब चड्ढा को आप में उप नेता के पद से हटाया गया, तब भी उन्हें भारी समर्थन मिला। बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के पति, राघव चड्ढा ने एक इंस्टाग्राम रील साझा की, जिसमें कई यूज़र्स द्वारा सुझाव दिया गया कि चड्ढा को अपनी खुद की ''जैन ज़ैड पार्टी'' बनानी चाहिये। रिहान नामक एक यूज़र ने भविष्यवाणी की थी।

चार दिन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके। केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने कहा कि केदारनाथ के कपाट खुले हुए आज चौथा दिन है और आज भगवान भैरवनाथ जी के कपाट भी खुल गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में केदारनाथ धाम में व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक हैं। प्रत्येक श्रद्धालु को दर्शन का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कुछ अराजक तत्व द्वारा धाम को बदनाम किया जाना बेहद निंदनीय है।

ईरान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने बैठक के कुछ दृश्य दिखाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें विदेश मंत्री इसाक दर और सेना प्रमुख आसिम मुनिर भी शामिल थे। वस्तुत: क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा के अस्पष्ट संदर्भ के अलावा, एजेंडे को लेकर कोई स्पष्टता नहीं थी।

तीन माह में चार छात्रों की मौत, एनआईटी कुरुक्षेत्र पर जाँच का शिकंजा कसा

16 फरवरी से 16 अप्रैल के बीच हुई इन चार घटनाओं से छात्रों, अभिभावकों व जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है

- पहली आत्महत्या 16 फरवरी को तेलंगाना के छात्र ने की थी, दूसरी घटना में 31 मार्च को हरियाणा ने नूह का छात्र, तीसरी घटना में 8 अप्रैल को सिरसा का तृतीय वर्ष का छात्र तथा 16 अप्रैल को बिहार की एक छात्रा मृत पाई गई थी।
- हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने घटना पर स्वत संज्ञान लेकर रिपोर्ट तलब की है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एआईसीटीई के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे के नेतृत्व में जाँच दल गठित किया है।
- पीड़ितों के परिजनों ने संस्थान के प्रशासन की कार्यशैली, होस्टल प्रबंध और छात्र कल्याण व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न उठाए।
- एनआईटी में 4 मई तक अवकाश घोषित कर दिया है और भारी प्रशासनिक फेरबदल भी किया गया है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो।

नई दिल्ली, 25 अप्रैल। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी-(नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नॉलजी अर्थात एनआईटी), कुरुक्षेत्र, पिछले दो महीनों में चार छात्रों की आत्महत्या और एक अन्य छात्र के 18 अप्रैल को होस्टल में कथित आत्महत्या के प्रयास के बाद, गहन जांच के घेरे में आ गया है। इस घटनाक्रम ने परिसर में आक्रोश पैदा कर दिया और इसके बाद कई आधिकारिक जांचें शुरू करवाई गईं।

हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने स्वेच्छा से मामले को संज्ञान में लिया और एनआईटी निदेशक, कुरुक्षेत्र के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी। आयोग ने निर्देश दिया है कि यह रिपोर्ट अगली सुनवाई से कम से कम एक हफ्ता पहले प्रस्तुत की जाए, अगली सुनवाई की तारीख 1 मई निर्धारित की गई है।

रिपोर्टों के अनुसार, कुछ पीड़ितों के माता-पिता और परिवार ने संदिग्ध गतिविधियों का आरोप लगाया और संस्थान प्रशासन, होस्टल प्रबंधन और छात्र कल्याण प्रणाली की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

मृतकों की श्रृंखला 16 फरवरी से शुरू हुई, जब तेलंगाना के एक प्रथम-सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस के छात्र को होस्टल कमरे में मृत पाया गया। दूसरा छात्र, जो हरियाणा के नूह का था, 31 मार्च को मृत पाया गया तथा 8 अप्रैल को सिरसा के तृतीय वर्ष के एक सिविल इंजीनियरिंग छात्र की मौत हुई, और नवीनतम घटना 16 अप्रैल को हुई, जब बिहार की द्वितीय वर्ष की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस छात्रा को उसके होस्टल कमरे में मृत पाया गया। 18 अप्रैल को आत्महत्या का प्रयास ने चिंता को और बढ़ा दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।

बढ़ते आक्रोश और चिंता के बीच, संस्थान ने सभी अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट और पीएचडी छात्रों को 19 अप्रैल तक होस्टल खाली करने का आदेश दिया और 4 मई तक अस्थायी शैक्षिक अवकाश घोषित किया। अधिकारियों ने कहा कि यह निर्णय छात्रों को घर जाने, परिवार के साथ समय बिताने और ताजगी भरे मनोबल के साथ पढ़ाई फिर से शुरू करने की सुविधा देने के लिए लिया गया।

हालांकि सैद्धांतिक परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेंगी, कुछ प्रायोगिक परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जा सकती हैं।

एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल में, एनआईटी प्रशासन ने अकादमिक, फैकल्टी वेलफेयर और रिसर्च एवं कंसल्टेंसी के डीन को बदल दिया है। होस्टल वॉर्डन और मुख्य वॉर्डन को भी बदला गया है। यह कदम छात्रों और माता-पिता की व्यापक आलोचना के बाद विश्वास बहाल करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

एनआईटी के वरिष्ठतम प्रोफेसर ब्रह्मजीत सिंह, जो निदेशक की अनुपस्थिति में एग्ज़ीग्यूटीव हैड हैं, ने कहा कि संस्थान संकट को गंभीरता से ले रहा है और तीन-स्तरीय सहायता संरचना लागू की है। उन्होंने कहा कि वार्डन रोजाना होस्टलों का दौरा करेंगे, प्रत्येक फैकल्टी मैंटॉर को 20-25 छात्रों का समूह सौंपा जाएगा, और हर होस्टल के लिए दो फैकल्टी मेंबर नियमित बातचीत और निगरानी के लिए जुड़े रहेंगे।

उन्होंने कहा कि अब हर छात्र को सीधे संवाद के लिए एक फैकल्टी मैंटॉर से जोड़ा गया है, जबकि विभागाध्यक्षों को अकादमिक या व्यक्तिगत शिकायतों का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। सिंह ने इन आरोपों को खारिज किया कि प्रोफेसरों ने छात्रों को धमकाया। उन्होंने कहा कि संस्थान संवाद के लिए खुला है।

इस बीच, केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी हस्तक्षेप किया है। इस सप्ताह दो अलग-अलग केन्द्रीय टीमों ने परिसर का दौरा किया। एक जांच पैनल, जो पूर्व एआईसीटीई अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे के नेतृत्व में था, ने छात्रों और फैकल्टी से मुलाकात की और मौतों के हालात की समीक्षा की। दूसरी केन्द्रीय टीम ने संस्थान में व्यापक प्रशासनिक मुद्दों की जांच की।

आयोग ने एनआईटी से कहा है कि वह प्रत्येक मृत्यु और आत्महत्या के प्रयास के पीछे की परिस्थितियों, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाओं की उपलब्धता और कार्यप्रणाली, तनाव या आर्थिक कठिनाई में छात्रों की पहचान का तंत्र, मेंटर-मेंटी प्रोग्राम का कार्यान्वयन, होस्टल सुरक्षा प्रोटोकॉल, अब तक उठाए गए निवारक कदम और अचानक होस्टलों को बंद करने और फैकल्टी को स्थानांतरित करने के कारणों की व्याख्या करे।

जिला प्रशासन और पुलिस से भी प्रत्येक मामले में जांच की रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि क्या किसी संस्थागत चूक या लापरवाही का इन घटनाओं में योगदान हो सकता है। इन घटनाओं ने मानसिक स्वास्थ्य, दबाव, अकादमिक तनाव, वित्तीय कठिनाई, होस्टल की स्थिति और भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में शिकायत निवारण तंत्र पर व्यापक राष्ट्रीय बहस को फिर से उभारा है।

ईरान में डिजिटल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

थी। नेटब्लॉक्स के आंकड़ों के मुताबिक, यह व्यवधान अब 1,344 घंटों की अवधि को पार कर चुका है। इससे पहले जनवरी 2026 में भी सरकार ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान इसी तरह की पाबंदी लगाई थी, जिससे आंतरिक अशांति की खबरें बाहर न जा सकें। इंटरनेट की इस लंबी अनुपस्थिति ने ईरान के आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। बैंकिंग सेवाएं, ऑनलाइन व्यापार और परिवहन नेटवर्क पूरी तरह ठप पड़े हैं।विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस शटडाउन से ईरानी अर्थव्यवस्था को अब तक 2.5 बिलियन डॉलर यानी23,570 करोड़ का कुल नुकसानहो चुका है। प्रतिदिन लगभग 370 करोड़ का राजस्व प्रभावित हो रहा है।

तेलंगाना...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गया था। इसके बाद उन्होंने एमएलसी पद और बीआरएस की प्राथमिक सदस्यता दोनों से इस्तीफा दे दिया था।बीआरएस से अलग होने के सात महीने बाद कविता ने अपनी नई पार्टी के लिए वही नाम टीआरएस चुना है, जिसके साथ उनके पिता ने कभी तेलंगाना राज्य आंदोलन की शुरुआत की थी। इस नाम के चयन को राजनीतिक रूप से बेहद प्रतीकात्मक माना जा रहा है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908